भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 296

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2026

पीएम विकास योजना का क्रियान्वयन

296. श्रीमती राजाथी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम विकास योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत वार्षिक बजटीय आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना की शुरूआत से विभिन्न राज्यों को आवंटित और जारी किए गए बजट का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना की शुरुआत से लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) योजना को लागू करने में सरकार द्वारा कौन-कौन सी चुनौतियों की पहचान की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन' (पीएम विकास) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित है:

i. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक)
ii. महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता
iii. शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से)
iv. अवसंरचना विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

इस योजना के दिशा-निर्देशों को जनवरी 2025 में अनुमोदन प्रदान किया गया था और तत्पश्चात योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 में बजट आवंटन और व्यय (आज की तारीख तक) का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
2024-25	255.43	30.00	0.00
2025-26	267.29	200.00	92.28

(ख) पीएम विकास का कार्यान्वयन केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में किया जाता है, और इसलिए, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधि आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय वर्तमान में केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से योजना के तहत पात्र एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है।

(ग): अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को लगभग 1.51 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। योजना की शुरुआत के बाद से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार योजना के लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ): पीएम विकास योजना का कार्यान्वयन जनवरी 2025 में शुरू किया गया है और लाभार्थियों के प्रशिक्षण सहित परियोजना कार्यान्वयन केवल चालू वित्तीय वर्ष में ही शुरू हुआ है। अत:, जैसे-जैसे योजना का कार्यान्वयन आगे बढ़ेगा, चुनौतियों, यदि कोई हों, की पहचान की जाएगी।

*****

"पीएम विकास योजना का क्रियान्वयन" विषय पर श्रीमती राजाथी द्वारा पूछे गए दिनांक 02.02.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 296 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएम विकास के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	3150
2	अरुणाचल प्रदेश	1860
3	असम	12020
4	बिहार	4725
5	छत्तीसगढ़	260
6	दिल्ली	9140
7	गोवा	270
8	हरियाणा	3250
9	जम्मू-कश्मीर	14960
10	झारखंड	8120
11	कर्नाटक	4885
12	केरल	1840
13	मध्य प्रदेश	10245
14	महाराष्ट्र	8995
15	मेघालय	7045
16	मिजोरम	210
17	नागालैंड	1550
18	ओडिशा	1400
19	पंजाब	16800
20	राजस्थान	3330
21	सिक्किम	210
22	तमिलनाडु	2000
23	तेलंगाना	3300
24	त्रिपुरा	1350
25	उत्तर प्रदेश	18080
26	उत्तराखंड	5780

27	पश्चिम बंगाल	6610
	कुल योग	**151385**